

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

क्षेत्रीय सर्वेक्षण अनुभाग (रा०प्र०स०)

क्षेत्रीय सर्वेक्षण (रा०प्र०स०) अनुभाग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय से सम्बन्धित व्यापक सामाजार्थिक आंकड़े सांख्यिकीय प्रतिचयन विधि (Statistical Sampling method) द्वारा एकत्रित करने के लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा०प्र०स०) का आरम्भ वर्ष 1950 से किया गया था। उ०प्र० का अर्थ एवं संख्या प्रभाग राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन०एस०ओ०), भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर वर्ष 1955 से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आँकड़े एकत्रित करा रहा है। समस्त प्रदेश में उक्त से सम्बन्धित आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराने, भारत सरकार से रिक्त अनुसूचियाँ तथा अनुदेश पुस्तिका भाग-१ व २ मंगाकर जनपदों में वितरण करना, जनपद स्तर पर आँकड़ों का परिनिरीक्षण कराने, क्षेत्र में आँकड़े की डाटा-इन्ट्री व वैलीडेशन कराने हेतु भारत सरकार से सॉफ्टवेयर प्राप्त कर कम्प्यूटर अनुभाग को उपलब्ध कराना, सर्वेक्षणकर्ताओं का निरीक्षण कराने तथा जनपदों से वैलीडेटेड आँकड़े प्राप्त कर समकं विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग-विश्लेषण अनुभाग (रा०प्र०स०) व संगणक अनुभाग को उपलब्ध कराने आदि का दायित्व प्रभाग मुख्यालय पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण (रा०प्र०स०) अनुभाग का है।

कार्य एवं उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन०एस०ओ०) द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाईयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा०प्र०स० के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यों को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

वर्ष 2023-24 में सम्पादित कार्य

रा०प्र०स०-७९वीं आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा०प्र०स०)-७९वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी। इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण-७९वीं आवृत्ति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1692 प्रतिदर्श इकाईयों द्वारा निम्न सामाजार्थिक विषय से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित कराया जाना था।

इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण-७९वीं आवृत्ति से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूचियाँ निर्धारित हैं-

अनुसूची 0.0CM : परिवारों की सूची (List of Households)

अनुसूची CAMS 2022-23 : व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण

(Comprehensive Annual Modular Survey-CAMS)

अनुसूची AYUSH 2022-23 : आयुष पर सर्वेक्षण (Survey on AYUSH)

इस आवृत्ति के अन्तर्गत अवशेष चतुर्थ आवृत्ति (01.04.2023 से 30.06.2023) में आवंटित 423 इकाईयों का सर्वेक्षण निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया गया। सर्वेक्षित इकाईयों के संग्रहित आँकड़ों में से प्रथम उपावृत्ति की अवशेष 11 इकाईयों, द्वितीय उपावृत्ति की अवशेष 109 प्रतिदर्श इकाईयों तथा चतुर्थ उपावृत्ति की समस्त 423 प्रतिदर्श इकाईयों के आँकड़ों की डाटा-इन्ट्री एवं वैलीडेशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया।

वैलीडेटेड डाटा के टैबुलेशन का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन०एस०ओ०), भारत सरकार से टैबुलेशन साफ्टवेयर प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। टैबुलेशन पूर्ण होने के पश्चात रिपोर्ट आलेखन किया जायेगा।

रा०प्र०स०-८०वीं आवृत्ति-

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा०प्र०स०), भारत सरकार द्वारा अनुदेश एवं निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जायेगा।

अर्थ व संख्या प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे सर्वेक्षण

Pilot survey on Labour Force Survey (LFS), Survey of Unincorporated Sector Enterprises (SUSE), Health, Education and corporate segment of service sectors

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ड्रिलिंग डॉलर बनाने के दृष्टिगत Bottom up approach से DDP के estimation हेतु जनपद स्तर पर Labour Force Survey तथा Survey of Unincorporated Sector Enterprises सर्वेक्षण कराया जाना के उद्देश्य से शासन के पत्र संख्या-I/390739/2023 कार्यान्वय दिनांक 19.09.2023 तथा साँख्यिकी एवं कार्यक्रम न मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या M-12011/17/2023-NSSO ;SCD) (E-63267) दिनांक-17.10.2023 के क्रम में जिला घरेलू उत्पाद के आंकलन के सम्बन्ध में methodology तैयार करने हेतु तथा जनपद स्तर पर कराए जाने वाले LFS एवं SUSE सर्वेक्षण के सम्बन्ध में pilot project के रूप में 04 जनपदों में सर्वेक्षण कराये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये विशेष सचिव नियोजन अनुभाग-2 द्वारा श्री आशीष कुमार, सेवानिवृत्त, महानिदेशक, CSO, भारत सरकार की अध्यक्षता में समिति गठित की गई।

समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में जनपद स्तरीय अनुमान प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर LFS, SUSE, Health, Education and corporate segment of service sectors के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में Pilot project के रूप में चयनित चार जनपदों हेतु समिति अध्यक्ष के निर्देशन में सर्वेक्षण की रूपरेखा, प्रतिदर्श आकार आदि का निर्धारण किया गया।

इसी क्रम में नियोजन अनुभाग-2, उ0प्र० शासन से जनपद वाराणसी, मेरठ, कानपुर नगर एवं गोरखपुर में LFS एवं SUSE का Pilot सर्वेक्षण AADISH Technologies and Softwares, Faridabad से निःशुल्क कराये जाने की अनुमति प्राप्त कर दिनांक 31.07.2024 तक LFS एवं SUSE के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराया गया। चारों जनपदों— वाराणसी, मेरठ, कानपुर नगर एवं गोरखपुर में LFS एवं SUSE हेतु आवंटित प्रतिदर्श निम्नानुसार थे—

District	Meerut		Varanasi		Gorakhpur		Kanpur Nagar		Total
Sector	LFS	SUSE	LFS	SUSE	LFS	SUSE	LFS	SUSE	
Rural	30	50	26	30	26	30	30	50	272
Urban	30	50	26	32	26	30	30	50	274
Total	60	100	52	62	52	60	60	100	546

चिकित्सा, शिक्षा तथा सेवा क्षेत्र के कॉर्पोरेट सेगमेंट का Pilot Survey चार जनपदों—मेरठ, वाराणसी, कानपुर नगर तथा गोरखपुर में माह अगस्त 2024 में से प्रारम्भ है।

Pilot Survey से प्राप्त परिणाम के उपरान्त ही प्रदेश के समस्त जनपदों में उपरोक्त सर्वेक्षण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।